इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना – Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS)

समाचार में क्यों / संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2025 में छह वर्षों के लिए Rs. 22,919 करोड़ के बजट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) को मंजूरी दी।
- हाल ही में इस योजना के तहत 249 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें Rs. 1.15 लाख करोड़ से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं, जो उद्योग जगत में इस योजना के प्रति गहरी रुचि को दर्शाती हैं।
- इसका उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन बढ़ाना, मूल्य संवर्धन बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और भारतीय निर्माताओं को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ जोड़ना है।

योजना का उद्देश्य

ईसीएमएस का मुख्य उद्देश्य भारत में एक **मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र** विकसित करना है। प्रमुख उद्देश्य हैं:

- बड़े घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना।
- विनिर्माण क्षमता और तकनीकी क्षमताओं का विस्तार करना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स में घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाना, जो वर्तमान में कुछ उत्पादों के लिए लगभग 15–20% है, और इसे सरकार 30–40% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
- वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण को सुगम बनाना।

Electronics scheme gets ₹1.15-lakh cr proposals

ENS ECONOMIC BUREAU
NEW DELHI, OCTOBER 2

THE CENTRE'S ambitious ₹23,000-crore electronics components manufacturing scheme has received 249 applications, with investment commitments totalling over ₹1.15 lakh crore, as it looks to fast-track incentives for increasing value addition in the country's burgeoning electronics sector.

The scheme, approved by the Union Cabinet in March with an outlay of ₹ 22,919 crore over six years, was expected to generate production of ₹4.56 lakh crore and bring in incremental investment of ₹59,350 crore.

Union minister Ashwini Vaishnaw

"Against a production target of ₹4,56,500 crore, we have received production estimates more than ₹10,34,000 crore" over the scheme's six year tenure, IT Minister Ashwini Vaishnaw told reporters Thursday. "For employment we have targeted 91,600 persons, but here the employment which is expected is one and a half times more at 1,41,000 persons."

The government is currently scrutinising the 249 applications — 60% of which have come from medium and small enterprises as per Vaishnaw — and will soon fasttrack approvals, though the minister did not offer a concrete timeline for it. He declined to reveal the names of the applicants due to the vetting process.

The components that the government is looking to target through the scheme are used in gadgets and appliances such as phones, laptops and fridges.

This incentive scheme differs from the government's earlier production-linked incentive scheme for electronics manufacturing in how participating firms can avail subsidies. Incentives have been linked to annual employment generation, capex needs and annual production.

लक्षित क्षेत्र

ईसीएमएस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, घरेलू उपकरण, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों पर केंद्रित है। लक्षित उत्पादों में शामिल हैं:

- **उप-असेंबली:** डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल।
- **प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)** और लचीले पीसीबी।
- **निष्क्रिय घटक:** प्रतिरोधक, संधारित्र, फेराइट।
- **लिथियम-आयन सेल एनक्लोजर** और अन्य आवश्यक पूंजीगत उपकरण।

यह योजना मुख्य रूप से निष्क्रिय घटकों को कवर करती है, जबकि सक्रिय घटक भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत आते हैं।

प्रोत्साहन संरचना

IAS-PCS Institute

यह योजना प्रोत्साहन के दृष्टिकोण में अनूठी है और इसे तीन प्रमुख मापदंडों से जोड़ा गया है:

- **टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन:** वृद्धिशील उत्पादन या बिक्री पर आधारित।
- **पूंजीगत व्यय-आधारित प्रोत्साहन:** संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए।
- **हाइब्रिड मॉडल:** दोनों का संयोजन, उद्योग की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित।

योजना की अवधि छह वर्ष है, जिसमें एक वर्ष का प्रारंभिक gestation period शामिल है। इसके साथ ही सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य रोजगार सृजन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

ईसीएमएस का महत्व

- **आर्थिक विकास:** इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसका वर्तमान मूल्य 150 बिलियन डॉलर से अधिक है और 2030 तक इसे 500 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
- **रोजगार सृजन:** योजना का उद्देश्य 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है, और वर्तमान अनुमानों के अनुसार मजबूत उद्योग भागीदारी के कारण यह संख्या 141,000 तक पहुँच सकती है।
- **तकनीकी उन्नति:** उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए घरेलू अनुसंधान एवं विकास, डिज़ाइन क्षमताओं और कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** रक्षा सहित महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए आयात पर निर्भरता कम करके रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** घटक उत्पादन का स्थानीयकरण करके भारत आयात पर निर्भरता कम कर सकता है और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।

घटक निर्माण में चुनौतियाँ

- **उच्च विनिर्माण लागत:** विभिन्न टैरिफ स्लैब और महंगे इनपुट के कारण।
- **स्केल-अप सीमाएँ:** कम जटिलता वाले या स्थानीय रूप से उत्पादित घटकों के लिए।
- **कमज़ोर अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत अनुसंधान पर सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम खर्च करता है, जबकि चीन और अमेरिका 2.5% से अधिक खर्च करते हैं।
- **आयात पर निर्भरता:** महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत तकनीक के लिए।

- **लंबी gestation period:** घटक उत्पादन में लंबा समय लगने से शुरुआती निवेश पर रिटर्न धीमा होता है।

आगे की राह

ईसीएमएस के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सरकार ने राजकोषीय और गैर-राजकोषीय दोनों तरह के कदम उठाए हैं:

- **राजकोषीय**: विनिर्माण के लिए पूंजीगत/संचालन व्यय सहायता, जटिल घटकों के लिए मिश्रित प्रोत्साहन, और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए नवाचार निधि।
- **गैर-राजकोषीय:** टैरिफ का युक्तिसंगत निर्धारण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सुविधा, शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, और कुशल प्रतिभाओं के आगमन में तेजी लाना।

निष्कर्ष

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके, कुशल रोजगार सृजित करके और भारतीय कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करके, यह योजना मूल्य संवर्धन, तकनीकी क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तैयार है। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ईसीएमएस भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, आयात पर निर्भरता कम कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना सकता है।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultm itra , 9235440806